नोएडा में फिर भड़का मजदूरों का प्रदर्शन

पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा, सेक्टर-80 में हिंसा, मजदूरों का बवाल

नोएडा, 14 अप्रैल. नोएडा सेक्टर 80 में एक बार फिर श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. सोमवार को हुई झड़पों के बाद पहले से सतर्क पुलिस ने मंगलवार को तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया.

इस दौरान कुछ श्रमिकों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की भी खबर सामने आई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया.यह विरोध ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

श्रमिकों को खुशखबरी- वेतन बढ़ोतरी का ऐलान

नोएडा. नोएडा और गाजियाबाद में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य सरकार की हाई पावर्ड कमेटी ने श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है. नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी. इसके तहत नॉन-स्किल्ड श्रमिकों को अब 13,690 रुपये, सेमी-स्किल्ड श्रमिकों को 15,059 रुपये और स्किल्ड श्रमिकों को 16,868 रुपये मासिक वेतन मिलेगा.

फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. यह पूरा घटनाक्रम हाल ही में घोषित न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी के बावजूद सामने आया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल मजदूरों की मासिक मजदूरी 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये कर दी है. 15,059 रुपये और कुशल मजदूरों को 16,868 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है. अन्य नगर निगम क्षेत्रों और जिलों में भी अलग-अलग श्रेणियों के लिए वेतन में वृद्धि की गई है.

आयकर विभाग ने 'फॉर्म 141' किया शुरू

नई दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 141 को शुरू किया है. यह एक कंसोलिडेटेड चालान-कम-स्टेटमेंट है, जो कि चार अलग-अलग टीडीएस फॉर्म का स्थान लेगा. यह नया फॉर्म, फॉर्म 26क्यूबी, फॉर्म 26क्यूसी, फॉर्म 26क्यूडी और फॉर्म 26क्यूई को मिलाकर बनाया है, जिनका उपयोग पहले क्रमश: संपत्ति की खरीद पर टीडीएस, किराए पर टीडीएस, ठेकेदारों या पेशेवरों को किए गए भुगतान पर टीडीएस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण पर टीडीएस दाखिल करने के लिए किया जाता था. नए संशोधित नियमों के मुताबिक, फॉर्म 141 का उपयोग अब 50 हजार प्रति महीने के भुगतान पर टीडीएस और 50 लाख की संपत्ति की खरीद पर टीडीएस जमा करने के लिए किया जा सकता है.

महिला आरक्षण समय की जरूरत : शाह

नई दिल्ली 14 अप्रैल. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू किये जाने को समय की जरूरत बताते हुए उम्मीद जतायी है कि सभी राजनीतिक दल इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करेंगे.

शाह ने महिला आरक्षण को लागू करने से संबंधित विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की नारी शक्ति को मंगलवार लिखे गये पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस पर प्रतिक्रिया करते हुए यह बात कही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक समय की आवश्यकता है। यह हमारी नारी शक्ति का उचित अधिकार है कि वे नीति निर्माण में योगदान दें और राष्ट्र को सशक्त बनाएं. मोदी सरकार इस विधेयक को लाने और लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो निश्चित रूप से बेहतर के लिए बिना किसी देरी के होना चाहिए।मुझे आशा है कि सभी लोग आगे आएंगे और इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करेंगे. उल्लेखनीय है कि श्री मोदी ने विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए संसद में गुरुवार को लाये जाने वाले संशोधन विधेयक से पहले नारी शक्ति को लिखे पत्र में कहा है कि यह भारत की नारी शक्ति के नाम मेरा पत्र है, जिसमें हम दशकों से लंबित इस कार्य को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं. अपने संदेश में श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया और नीतिगत उपायों तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर सरकार के ध्यान को रेखांकित किया है. उल्लेखनीय है कि सरकार विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए इस में संशोधन के लिए गुरुवार को संसद में विधेयक लाने जा रही है.

चांदखेड़ी में लहराया महाकोशल-विंध्य का परचम

चांदखेड़ी राजस्थान। जैन अतिशय तीर्थ स्थल चांदखेड़ी में दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का 30 वां राष्ट्रीय अधिवेशन अत्यंत भव्यता एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। देशभर से पधारे पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस अधिवेशन में महाकोशल-विंध्य रीजन ने अपने उत्कृष्ट कार्यों के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित की। अधिवेशन के दौरान महाकोशल-विंध्य रीजन के अध्यक्ष सीए मनोज जैन को सर्वश्रेष्ठ रीजन अध्यक्ष के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया, वहीं रीजन के कोषाध्यक्ष सुनील घिया को सर्वश्रेष्ठ कोषाध्यक्ष के रूप में सम्मानित

किया गया। यह उपलब्धियाँ वर्ष 2025 में रीजन द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उत्कृष्ट कार्यों का प्रतिफल हैं। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नितिन जैन एवं राष्ट्रीय सहसचिव संजय सम्यक ने बताया कि जबलपुर के विभिन्न सोशल ग्रुप्स ने अपने उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर कुल 26 अवार्ड प्राप्त कर रीजन का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। जबलपुर मेन ग्रुप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 अवार्ड अपने नाम किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष का सम्मान मुल्कराज बादशा को प्राप्त हुआ। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं स्क्रैप बुक श्रेणी में द्वितीय स्थान भी हासिल किया।

इनका किया गया सम्मान

अधिवेशन की भव्य स्मारिका 'चंद्रोदय घोष' के उत्कृष्ट एवं त्रुटिरहित संपादन के लिए प्रधान संपादक प्रशांत जैन सहित संपादकीय टीम-डॉ. यतीश जैन, गोपाल जैन, संजय सम्यक, विकास जैन एवं अंजुल जैन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं जबलपुर नगर ग्रुप ने भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए कुल 12 अवार्ड प्राप्त किए। ग्रुप के अध्यक्ष प्रफुल्ल-रीता जैन को श्रेष्ठ अध्यक्ष का सम्मान मिला।

सरकार के राष्ट्रव्यापी अभियान को मिली सफलता

नवभारत जबलपुर। भारत सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाज़ारी पर रोक लगाने के लिए अपने सिस्टम को काफ़ी मज़बूत बनाया है। साथ ही सरकार ने देश भर में वास्तविक उपभोक्ताओं तक बिना किसी रूकावट के स्वच्छ ईंधन पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत, सिर्फ 11 अप्रैल, 2026 को 2,700 से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर छापे मारे गए। इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य अनियमितताओं का पता लगाना, घरेलू एलपीजी के गलत इस्तेमाल को रोकना और वितरण नेटवर्क में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के अचानक इंस्पेक्शन के साथ अपनी निगरानी तेज़ कर दी है। इन कड़े निरीक्षणों के बाद, 219 डिस्ट्रीब्यूटरों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि तय नियमों का उल्लंघन करने वाले 56 डिस्ट्रीब्यूटरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

पूरे देश में 52.3 लाख से ज़्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति -इसके साथ ही ओएमसी ने ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को बढ़ावा देने और लास्ट-माईल पहुँच सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को जागरुक बनाने के प्रयासों को भी बढ़ाया है। पिछले आठ दिनों में लगभग 3,300 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से 5 किलोग्राम वाले 'फ्री ट्रेड एलपीजी' (एफटीएल) सिलेंडरों की उपलब्धता और उन्हें अपनाने पर ज़ोर दिया गया है; इन अभियानों के दौरान ऐसे 35,800 से ज़्यादा सिलेंडर बेचे गए। ये सभी प्रयास प्रवासी और वंचित आबादी की जरूरतों को पूरा करने औरघरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं। सिर्फ 11 अप्रैल 2026 को पूरे देश में 52.3 लाख से ज़्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई। यह आँकड़ा दुनिया भर में बदलती परिस्थितियों के बावजूद भी निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।

सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान

अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की : मोदी

नई दिल्ली, 14 अप्रैल. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

बिरला ने डॉ. अम्बेडकर के प्रमुख योगदानों का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान में समानता का अधिकार तथा बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार जैसे प्रगतिशील प्रावधानों ने एक सशक्त भारत की नींव रखी, जो न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि विश्व के अन्य लोकतंत्रों को भी निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। भारत के युवाओं को बाबासाहेब के विचारों का सच्चा प्रतिनिधि बताते हुए उन्होंने उन्हें सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया.

अंबेडकर जयंती पर राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश

नई दिल्ली. नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ अंबेडकर ने भारत को केवल संविधान ही नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित एक मजबूत राष्ट्र का सपना भी दिया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में आरोप लगाया कि आज कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से बाबासाहेब की विरासत और संविधान को कमजोर करने में लगी हैं. लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है.

अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है सरकार की योजनाएं : नितिन

नई दिल्ली.भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को कहा कि सरकार की योजनाएं बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है और इसी का अनुकरण करते हुए केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रही है. नितिन ने आज यहां भाजपा मुख्यालय में संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलित अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

सरकारी नौकरियों में समानता के अधिकार का पालन करना अनिवार्य

नई दिल्ली, 14 अप्रैल. उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि अगर सेवा नियमों में अनुभव, योग्यता या वरिष्ठता के आधार पर छूट का प्रावधान है, तो किसी कर्मचारी को केवल डिग्री न होने की वजह से प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता.

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक सहकारी समिति के कर्मचारी को पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने माना कि जब अन्य कर्मचारियों को समान छूट दी गई, तो इस मामले में शैक्षिक योग्यता में रियायत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि भेदभाव अन्याय का ही दूसरा नाम है. अदालत ने जोर दिया कि सरकारी नौकरियों में समानता के अधिकार का पालन करना अनिवार्य है. न्यायालय ने यह टिप्पणी एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के कर्मचारी से जुड़े मामले के दौरान की, जिसने लगभग तीन दशकों तक सेवा की थी.

राहुल ने नोएडा में वेतन बढ़ाने के श्रमिक आंदोलन को सही ठहराया

नई दिल्ली, 14 अप्रैल. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोएडा में श्रमिकों के वेतन बढ़ाने को लेकर किए गए आंदोलन को सही ठहराते हुए कहा है कि आसमान छूती महंगाई के साथ मजदूरी बढ़ाने की बात वाजिब है और उनकी इस मांग पर संवेदनशीलता के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए.

पश्चिम मध्य रेल

विद्युत विभाग(कर्षण-वितरण शाखा) जबलपुर ▪ ई-निविदा सूचना

एन.आई.टी. नं. जबल-टीआरडी-निविदा-2025-09R, दिनांक 08.04.2026

वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण-वितरण/ पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित करते है। ठेकेदारों के पास राज्य सरकार द्वारा जारी विद्युतीय लायसेन्स (फर्म के नाम से या फर्म के किसी पार्टनर के नाम से या स्वयं के नाम में यदि सोल प्रोपराइटर हों) आई.ई. नियम 1956 के अनुसार होना चाहिए। **1. कार्य का नाम: (क) जबलपुर डिवीजन (चरण-1) के सहायक ट्रांसफार्मर के लिए अलग से स्पेयर केबल की व्यवस्था। (ख) मौजूदा अप और डाउन मुख्य लाइनों और नई तीसरी लाइन में हरदुआ-नए मझगवां फाटक के बीच आईबीएस की व्यवस्था। (ग) रतोना में पुराने और अप्रचलित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने के लिए एटी आपूर्ति की व्यवस्था। 2. कार्य स्थल:** जबलपुर मण्डल। **3. कार्य की अवधि:** 12 माह। **4. कार्य की कीमत (टेंडर वेल्यू):** ₹ 1,97,86,466.67 (रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख छियासी हजार चार सौ छियासठ और सड़सठ पैसे मात्र)। **5. बयाना राशि:** ₹ 3,95,700/-. **6. निविदा जमा करने/खुलने की अंतिम तिथि एवं समय:** 04.05.2026, 15.00 बजे/04.05.2026, 15.30 बजे। **7. निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेल्वे वेबसाईट: https://www.ireps.gov.in. 8.** निविदाकर्ता अपनी निविदाऐं आई आर ई पी एस की माध्यम से **https://www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन निविदा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे समय समय पर बदलाव व शुद्धिपत्रों हेतु IREPS की वेबसाईट **https://www.ireps.gov.in** देखते रहें। न्यूनतम पात्रता मानदण्ड टेण्डर फार्म के अनुसार और ज्वांइन्ट वेन्चर व साझेदारी इस निविदा के लिए लागू होगा।

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

सिविल इंजीनियरिंग (निर्माण) ई-निविदा सूचना ▪ खुली निविदा ई.पी.सी. [सिंगल स्टेज] टू पैकेट

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से **उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेल, सतना,** निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करते है। **क्र.स.:** 1. **निविदा संख्या: डिप्टी. सी.ई.सी.-द्वितीय-सतना-01-2026. कार्य का विवरण: मध्य प्रदेश राज्य में सतना-पन्ना नई रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत, सकरिया रोड - पन्ना खंड में 03 वायाडक्ट और 02 एनिमल क्रॉसिंग का निर्माण; देवेन्द्र नगर - सकरिया रोड - पन्ना खंड में (वन क्षेत्र में) चेन - लिंक फेंसिग का कार्य; सतना-नागोद खंड में 03 कैनाल क्रॉसिंग और 02 आर.ओ.बी. तथा रिटेनिंग वॉल का निर्माण तथा अन्य संबंधित विविध कार्यों के लिए ई.पी.सी. निविदा। प्रथम प्रि-बिड कॉन्फ्रेंस दिनांक** – 27.04.2026, समय 11.00 बजे। **द्वितीय प्रि-बिड कॉन्फ्रेंस दिनांक** – 11.05.2026, समय 11.00 बजे। **स्थान** - मुख्य अभियंता/सी-IV/मुख्यालय/प.म.रे. का कक्ष, सेकेन्ड फ्लोर, जी.एम. ऑफिस बिल्डिंग, जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास। **निविदा बन्द होने की तारीख:** 08.06.2026. **अनुमानित लागत:** ₹ 142,07,27,058.13. पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड की गई ई-निविदा में तथा उप मुख्य अभियंता, पश्चिम मध्य रेल, सतना के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई-निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। ई-निविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संख्या – डिप्टी.सी.ई.सी-द्वितीय-सतना-निविदा आमंत्रण सूचना-01-2026, दि. 10.04.2026

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

तमिलनाडु में भाजपा का चुनावी घोषणापत्र जारी

परिवार की महिला मुखियाओं को 2000 रुपये

ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 की आर्थिक मदद

चेन्नई,14 अप्रैल. तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्ना द्रमुक) की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

भाजपा की ओर से जारी घोषणा पत्र में कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की गयी, जिनमें से कुछ अहम योजनाएं वैसी ही हैं जैसी सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने पेश की थीं। भाजपा ने हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये और हर परिवार को एक बार में 10,000 रुपये की नकद सहायता देने का वादा किया है, ताकि महंगाई के दबाव से राहत मिल सके। इसके अलावा, पार्टी ने साल में तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया है। पार्टी ने योग्य महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का भी संकल्प लिया है।

एक ओर जहां द्रमुक ने राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं को दी जाने वाली मौजूदा 1,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का आश्वासन दिया है, वहीं अन्ना द्रमुक ने भी अपने घोषणापत्र में इस राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा, अन्ना द्रमुक ने अभी केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को पुरुषों के लिए भी शुरू करने का वादा किया है.

ईसीआई ने 727 .58 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की

चेन्नई. निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के उड़न दस्ते और सर्विलांस टीम के अधिकारियों ने तमिलनाडु में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखते हुए 727.58 करोड़ रुपये की नकदी एवं अन्य सामग्री ज़ब्त की है, जिसमें शराब और ज्वैलरी भी शामिल हैं.

तमिलनाडु में 234 सदस्यों वाली 17वीं विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं.मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने मंगलवार को कहा कि चुनाव कराने में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के लिए, ईसीआई ने चुनावों के लिए 326 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं.इनमें 136 सामान्य पर्यवेक्षक, 40 पुलिस पर्यवेक्षक और 151 व्यय लेखा पर्यवेक्षक शामिल थे और उन्हें तमिलनाडु के 234 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया गया था.केन्द्रीय पर्यवेक्षक के संपर्क विवरण की जानकारी संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के ज़रिए दी गई हैं, ताकि नागरिक, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सीधे चुनाव से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकें या उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकें.उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव खर्च की कड़ी निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि निगरानी और प्रर्वतन टीमें पूरे राज्य में सक्रिय रूप से तैनात हों ताकि नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और दूसरी प्रतिबंधित चीजों सहित गैर-कानूनी प्रलोभन सामग्री पर नज़र रखी जा सके और उन्हें रोका जा सके.इन तेज प्रर्वतन उपायों के नतीजे में 13 अप्रैल तक तमिलनाडु में कुल मिलाकर 727.58 करोड़ रुपये की ज़ब्ती हुई है.इसमें 126.64 करोड़ नकद शामिल है.2.36 करोड़ की शराब, ड्रग्स/नारकोटिक्स 75.48 करोड़ रुपये, कीमती धातु 295.46 करोड़ रुपये और दूसरी चीज़ें और मुफ्त चीज़ें 226.15 करोड़ रुपये हैं.सुश्री अर्चना पटनायक ने कहा कि जब्त की गई कुल रकम में से 381 करोड़ रुपये सही दस्तावेज जमा करने पर बिना किसी परेशानी के जारी कर दिए गए हैं.

बंगाल विस चुनाव में 2,926 उम्मीदवार मैदान में

नयी दिल्ली/कोलकाता. चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है.

चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद राज्य में कुल 2,926 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर 1,478 उम्मीदवार और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1,448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल थी, जबकि 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटिनी) और 13 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी .चुनाव कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को कराया जाएगा .सभी निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत उम्मीदवारों की अंतिम सूची सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करेंगे. आयोग ने बताया कि सभी रिटर्निंग अधिकारी चुनावी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए नामांकन, जांच और नाम वापसी से जुड़े रिकॉर्ड को सीलबंद पैकेट में सुरक्षित रखेंगे .मतदाताओं की सुविधा के लिए ईसीआई ऐप नेट पर %अपने उम्मीदवार को जानें% की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

बांग्ला-विरोधी के खिलाफ मजबूती जरूरी : ममता

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने विपक्षी दल को 'बांग्ला-विरोधी जमींदार' बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा राज्य के लोगों को बांटने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी रैली का वीडियो साझा करते हुए बीरभूम, पूर्व और पश्चिम बर्धमान तथा बांकुड़ा के मतदाताओं से टीएमसी को चौथी बार सत्ता में लाने की अपील की. ममता ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में जो कुछ भी हासिल हुआ, वह मां-माटी-मानुष की साझी ताकत का नतीजा है। उन्होंने सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि बांग्ला-विरोधी जमींदारों के खिलाफ मजबूत दीवार बनकर खड़ा होना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने भाजपा और अन्य ताकतों पर राज्य को बदनाम करने और लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया. ममता ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनके भाई-बहन उनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं और राज्यवासियों के प्यार और आशीर्वाद ने उन्हें सशक्त बनाया है। उन्होंने यह भरोसा जताया कि मां-माटी-मानुष सरकार चौथी बार ऐतिहासिक वापसी करेगी।

देहरादून एक्सप्रेस से विकास को मिलेगी गति

देहरादून, 14 अप्रैल. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण देश के विकास का प्रतीक है और इससे राष्ट्रीय राजधानी तथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच की दूरी आठ घंटे से घटकर महज छह घंटे की रह जाएगी.

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि इस परियोजना में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और वन्यजीवों की आवाजाही को विशेष महत्व दिया गया है ताकि विकास की गतिविधियों से वन्य जीवों की स्वच्छंदता बाधित नहीं हो. वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में एक्सप्रेसवे को एलिवेटर से जोड़ा गया है वन्य जीव जंतु आसानी से और स्वच्छंदता के साथ विचरण कर सकें.

जाम की स्थिति से निपटने के लिए परियोजना को मंजूरी

देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार में जाम की स्थिति से निपटने के लिए भी परियोजना को मंजूरी दी गई है और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा.हरिद्वार , देहरादून और ऋषिकेश के बीच लोगों को जाम के संकट से छुटकारा मिले और आवाजाही को आसान बनाया जाय इसके लिए बेहतर और चौड़ी सड़कों के निर्माण के साथ ही विकास की नयी नयी योजनाओं को पूरा किया जा रहा है.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तराखंड में विकास को नया आयाम मिलेगा. 12000 करोड़ की लागत से निर्मित इस परियोजना से उत्तराखंड में यातायात सुविधा अत्यंत आधुनिक हो जाएगी.

और चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए भी इससे आवाजाही और आसान हो जाएगी.उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा और बेहतर हो जाएगी.श्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में भूस्खलन के संकट से निपटने की परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है और खासकर केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाने के वास्ते रोप-वे बनाए जा रहे हैं.इन परियोजनाओं के जरिए दोनों धाम की यात्रा अत्यंत आसान हो जाएगी.इससे केदारनाथ में आधा घंटे में 9 घंटे के सफर को तीर्थ यात्री आसानी से पूरा कर सकेंगे.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए **19/05/2026 से 21/05/2026** तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
175109693	असलम खान	जबलपुर विजय नगर
168395250	असलम खान	जबलपुर विजय नगर

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :
1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

दिनांक: 15.04.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी